

तो लगभग थोड़ा बहुत अंतर आता है कोई अधिक का अंतर नहीं आता है। ....(व्यवधान)....

**श्री नीलोत्पल बसु :** एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि फूड प्रोडक्शन घट रहा है।

**श्री सभापति :** ठीक है, हो गया।

**श्री नीलोत्पल बसु :** फिर भी हमारा स्टॉक इतना ज्यादा है। यह तो अपने आप में एक विरोधाभास है। फूड सिक्योरिटी में भी खतरा है, आप इसको पहचानने से इन्कार कर रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे चिंता का विषय है कि लगातार सात साल से फूड प्रोडक्शन घट रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है इसलिए वे खरीद नहीं पा रहे हैं। इसके चलते फूड स्टॉक बढ़ गया है और इसके बावजूद आप फूड सिक्योरिटी को जो खतरा पैदा हो रहा है, इसको पहचानने से इन्कार कर रहे हैं। यह तो देश के लिए एक बिकट परिस्थिति पैदा हो गई है।

**श्री सभापति :** ठीक है, ठीक है।

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** सभापति महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य उठा रहे हैं। इसमें संबंधित एक प्रश्न आज ही है जिसमें खाद्य सुरक्षा और अन्य चीजों की चर्चा है। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर अन्न खाना कम हुआ है तो दूसरी चीजें खा रहे हैं।

### Foreign universities

\*184. SHRI NANA DESHMUKH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of foreign universities that are operating in one way or the other in India giving details of the number and the name of country of their origin; and

(b) what precautions have been taken to grant approval to such foreign universities before their entry in India?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) and (b) A recent study of three leading newspapers in which advertisements of foreign universities were published, conducted by National Institute of Education Planning and Administration (NIEPA), revealed that 50 universities of USA, 39 universities of UK, 26 universities of Australia and 7 universities of New Zealand are marketing their programmes in India. Various types of arrangements ranging from franchise, tie-ups, twinning to external campus are on offer.

According to an earlier survey, Association of Indian Universities (AIU), scanned 14 national newspapers over a six-month period (1st July-31st Dec 2000) for advertisements, by foreign education providers, related to higher education opportunities. According to this survey, 144 foreign universities/colleges/institutions were offering various courses of study to the Indian students. Out of them 117 offered programmes on their home campuses and the remaining 27 were conducting programmes in India through their Indian partners. The largest number of these institutions were from UK (53) and Australia (40) followed by USA (24), Canada (7) and New Zealand (5). The remaining institutions were from various other countries like Bulgaria, Cyprus, Hong Kong, France, Ireland, Mauritius, Nepal, Russia and Switzerland.

The University Grants Commission (UGC) has proposed regulations for entry and operation of foreign universities/educational institutions in India and necessary amendments to the UGC Act are under consideration of Government.

However, All India Council for Technical Education (AICTE) has issued Regulations for entry and operation of foreign universities/institutions in India imparting technical education. According to these regulations "no foreign university/institution shall establish/operate its educational activity in India leading to award of diplomas/degrees including post-graduate and doctoral without the express permission/approval of the Council". Further, any Application for registration of foreign universities/institutions imparting/intending to impart technical education in India shall be *inter-alia* accompanied with the No objection certificate from the concerned Embassy in India,

Accreditation certificate of the foreign university/institution by the authorised agency in the parent country and an undertaking from the foreign university/institution stating that the degree/diplomas awarded to the students in India is recognised in the parent country etc.

**श्री सभापति :** ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 श्री नाना देशमुख।

**श्री नाना देशमुख :** सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश में डेढ़ सौ से अधिक संख्या में विदेशी विश्वविद्यालयों को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुमति देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दुनिया में जो बदनाम है, जैसे यू.के. के 50 से अधिक विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया के 45 विश्वविद्यालय, अमेरिका के लगभग 30 विश्वविद्यालय हमारे देश में काम कर रहे हैं। यह इसी विभाग के प्रोफेसर राजशेखरन पिल्ले कह रहे हैं। इसकी क्या आवश्यकता है कि हमारे देश में लगभग डेढ़ सौ से अधिक विदेशी विश्वविद्यालय आकर काम करें? क्या हम अपने देश लगभग डेढ़ सौ से अधिक विदेशी विश्वविद्यालय आकर काम करें? क्या हम अपने देश में विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में समर्थ नहीं हैं?

**डा. मुरली मनोहर जोशी :** सभापति महोदय, जो विश्वविद्यालय यहां काम कर रहे हैं, वे तीन प्रकार से काम करते हैं। इसमें से एक बड़ा प्रकार यह है कि वे यहां से छात्रों को भर्ती करके विदेश ले जाते हैं, वे यहां पढ़ाते नहीं हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके यहां के विश्वविद्यालयों से करार है। उस करार के मुताबिक उनके पाठ्यक्रम यहां और हमारे पाठ्यक्रम वहां—जिसे विश्वविद्यालयों की ट्विनिंग कहते हैं, उसके अंतर्गत है। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिन्हें उन्होंने अपना फ्रेंचाईज दिया हुआ है, उनकी संख्या बहुत कम है। इस प्रकार ऐसे लोग जो यहां पढ़ा रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। हमने जो सर्वे अभी तक कराया है, उसके अनुसार जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके अधिकांश लोग वे हैं जो छात्र भर्ती करके यहां से ले जाते हैं। जो यहां अपने परिसर बनाकर पढ़ाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। हमने इसके लिए प्रबंध किए हैं और फिलहाल अभी एआईसीटीई की तरफ से वे सारे प्रतिबंध जारी कर दिए गए हैं जिनके अंतर्गत रहकर वे यहां काम कर सकेंगे और वे इस प्रकार के होंगे जिनमें केवल उचित और सही लोग ही यहां काम कर पाएं।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह हिदायत कर दी गयी है कि वह अपने ऐक्ट में संशोधन कराए और उसके मुताबिक अपने नए रेगुलेशंस जारी करें। हम इस संबंध में बहुत चिंतित हैं क्योंकि हमें इस बारे में खबरें मिलती हैं कि बहुत अधिक मात्रा में फीस इस देश से बाहर जा रही है। उसको भी हम रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि शीघ्र ही दम सदन के सामने उस कानून के साथ आएंगे।

DR. KARAN SINGH: Mr. Chairman, Sir, one of the reasons why there is a demand for foreign universities is that our universities are always unable to meet the demand. There has been a longstanding scheme to enable the private universities in India to function in order to fulfil the demand. So far, the universities are the monopoly of the State. In a democratic world private universities also have an important role to play. Now, for some reason the hon. Minister seems to be reluctant to bring the Private Universities Bill before the Parliament. May I enquire from him, through you, Sir, as to when he is going to bring forth the Private Universities Bill and whether, instead of being so reluctant, he will show a little enthusiasm and bring forth the Bill quickly?

**डा. मुरली मनोहर जोशी :** सभापति महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। एचआरडी की जो संसदीय समिति है, उसने उस बिल का पूरे तौर पर निरीक्षण किया था जो यहां आया और उन्होंने उसमें ऐसे बहुत से प्रावधान पाए जो ठीक नहीं हैं और मैं भी समझता हूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के निर्माण के बारे में बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अभी भी कुछ राज्यों ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने के कानून बना दिए हैं – उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं, छत्तीसगढ़ ने बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में एक दम से 36 यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं। अब वे पता नहीं कैसे चलेगी, क्या होगी, क्या नहीं होंगी? मैं माननीय सदस्य की आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों का निर्माण बहुत सोच समझकर हो, ठीक ढंग से हो, वे क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, वे शिक्षा की दुकानें न बनें, वे शिक्षा का व्यापारीकरण न करें, इस बात को ध्यान में रखकर भी किया जाता है। लेकिन हमने यूजीसी में ऐसी व्यवस्थाएं की हुई हैं, जिनके आधार पर कॉलेजों के विस्तार में, विश्वविद्यालयों के विस्तार में कोई दिक्कत नहीं है। अभी 90 के करीब डीमड-टू-बी यूनिवर्सिटीज हमारे देश में काम कर रही हैं, ऑटोनॉमस कॉलेजों की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि शिक्षा की क्वालिटी और शिक्षा के व्यापारिकरण के साथ यह सरकार सहमत नहीं है और ऐसी किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, जो एक प्रकार से चल रही है, हम ठीक ढंग से, विश्लेषण करेंगे, जानकारी लेंगे और उसको एक शॉप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम नहीं करने देंगे।

SHRI R. SHUNMUGASUNDARAM: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether there is any proposal from the Government side to invite any foreign university which offers

specialised course on any particular science subject which is not offered by our universities in India.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: There is no such proposal before the Government. If there is any such course which is not available in this country and which is available outside, the Government will try to introduce that course in the country itself.

### **Srinagar rail project**

\*185. SHRIMATI AMBIKA SONI:†

DR. ABRAR AHMED:

Will the Minister -of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the prestigious Srinagar rail project is progressing as per schedule;

(b) if so, its status as on date; and

(c) by when the first train is expected to reach Kashmir?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

### **Statement**

(a) and (b) There are two new rail line projects in progress in Jammu & Kashmir for providing rail connection from Jammu to Baramulla via Katra, Qazigund, Srinagar. The status of the two projects is as under:

(i) JAMMU-UDHAMPUR (53.6 KM)-Jammu to Bajalta (11 km) has already been completed. In the remaining section, earthwork and tunneling has been completed. Bridge work, track Jinking and other works are in progress. The project is targeted for completion by March 2004.

(ii) UDHAMPUR-SRINAGAR-BARAMULLA (287 km)-This project is under progress in three phases as under:

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Ambika Soni.